AKSH OPTIFIBRE LIMITED

A-32, 2 Floor,
Mohan Co-operative Industrial Estate, Mathura Road,
New Delhi-110044, INDIA
Tel.: +91-11-49991700, 499917777
Fax : +91-11-49991800
Email : aksh@akshoptifibre.com
Website : www.akshoptifibre.com
CIN NO. : L24305RJ1986PLC016132

May 20, 2023

To,

National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra(E), Mumbai – 40005 **Scrip Code: AKSHOPTFBR**	**BSE Limited** Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Bombay-400 001 **Scrip Code: 532351**

Subject: Submission of Newspaper Publication

Dear Sir/Madam,

Please find enclosed copies of Newspaper Publication of "Audited Financial Results (Standalone & Consolidated) for the quarter and financial year ended March 31, 2023 published in "The Financial Express" and "Lokmat" on May 20, 2023, in compliance with Regulation 30 & 47 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulation, 2015.

Kindly take the same on records.

***for* Aksh Optifibre Limited**

ANUBHHAV RAIZADA Digitally signed by ANUBHHAV RAIZADA Date: 2023.05.20 16:18:12 +05'30'

Anubhhav Raizada
Company Secretary

Encl: a/a

● EQUITY DERIVAT

Sebi man risks for i

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, May 19

SEBI ON FRIDAY decided to introduce risk disclosure framework for individual traders with respect to trading in the equity futures and options (F&O) segment, with an aim to facilitate informed decision making by investors,.

The new framework would come into force from July 1, Sebi said in a circular. Under it, all stock brokers will have to display the risk disclosures on their websites and also inform all their clients in the specified manner.

Upon login into their trading accounts with brokers, clients may be prompted to read the 'risk disclosures' — which may appear as a pop-up window — and would be allowed to proceed ahead only after acknowledging the same.

Further, such disclosures should be displayed promi-

INV

■ All
have
discl
web
infor
the s

nently
area of
Seb
been in
investo

'Small-ticket could give pay bank model a

PIYUSH SHUKLA
Mumbai, May 19

PAYMENTS BANKS TOUCH the lives of more than 100 million consumers each month, and enabling such players to offer small-ticket micro loans from their own balance sheets could significantly boost the viability of the model and enable more financial inclusion, Airtel Payments Bank managing director and chief executive officer Anubrata Biswas told fe on Friday.

"Today, if the payment bank

Airtel
CEO A

and c
produ
fee in

Muthoot Finance profit falls 6%

FE BUREAU
Chennai, May 19

GOLD LOAN MAJOR Muthoot Finance on Friday posted a standalone net profit of ₹903 crore for Q4FY23, compared with ₹960 crore for the year-ago period, registering a decline of 6%.

The standalone income stood at ₹2, 864 crore, compared to ₹2,678 crore, an increase of around 7%. Gold loan assets stood at ₹61,875 crore, against ₹57,531 crore, registering a growth of 8%.

Consolidated net profit was flat at ₹1,009 crore, against ₹1,006 crore in the corresponding quarter of last fiscal.

George Alexander Muthoot, MD, said, "The gold loan assets growth during Q4 FY23 was the highest ever for any fourth quarter. Disbursements, too, stood historic high for any Q4 at ₹51,850 crore. Increase in Stage 3 assets is purely an accommodation given to customers for a few more months on the back of higher collateral value, and we do not envisage any loss on account of the extended time."

The board has approved an interim dividend of 220%, that is, ₹22 per equity share of ₹10, involving a payout of ₹883 crore for FY 23.

George Jacob Muthoot, chairman, Muthoot Group, said, "Our vision is to remain the leader in gold loan business, and at the same time, cater to a large customer base with various loan products to meet their varied requirements. In this process, we expect to grow the loan book by 10-15% during FY 24."

Muthoot Finance has launched small business loans to address the prevailing gap of credit access to the MSME segment with unsecured loan ticket size of up to ₹10 lakh.

जयपुर में 26 दिनों में 3 लाख से ज्यादा परिवारों ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए करवाया रजिस्ट्रेशन

जयपुर। आमजन को महंगाई से राहत दिलाने में राजस्थान सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन कारगर साबित हो रहीं है, सिर्फ 26 में ही जयपुर जिले में 3 लाख से ज्यादा परिवारों ने प्रतिमाह न्यूनतम 1000 रुपये सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए, महंगाई राहत कैंप में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है।

अब तक 38 लाख से ज्यादा मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड हुए जारी

कलक्टर श्री प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि महंगाई राहत कैंप 24 अप्रैल को शुरू हुए थे जिसके बाद अब तक कुल 38 लाख 82 हजार 344 गारंटी कार्ड जारी किये जा चुके हैं। मुख्यमंत्री नि:शुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत 5 लाख 68 हजार 525, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में 7 लाख 53 हजार 540, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 7 लाख 53 हजार 540, मुख्यमंत्री नि:शुल्क कृषि बिजली योजना में 60 हजार 577, मुख्यमंत्री नि:शुल्क घरेलू बिजली योजना में 6 लाख 59 हजार 835 लाभार्थियों को गारंटी कार्ड जारी हुए हैं।

वहीं, महंगाई राहत कैंप में मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना में 3 लाख 92 हजार 367, इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में 2 लाख 8 हजार 304, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 3 लाख 1 हजार 343, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में 1 लाख 59 हजार 876, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 24 हजार 437 लाभार्थियों ने पंजीकरण करवाया है।

शुक्रवार को वितरित किये गए 1 लाख 8 हजार से ज्यादा गारंटी कार्ड

उन्होंने बताया कि शुक्रवार को 1 लाख 8 हजार 989 गारंटी कार्ड जारी किये गए। जिसमें से अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत 14 हजार 780, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में 19 हजार 968, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 19 हजार 968, मुख्यमंत्री नि:शुल्क कृषि बिजली योजना में 1 हजार 811, मुख्यमंत्री नि:शुल्क घरेलू बिजली योजना में 16 हजार 746 लाभार्थियों को गारंटी कार्ड जारी हुए हैं।

वहीं, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना में 15 हजार 471, इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में 5 हजार 713, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 7 हजार 652, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में 6 हजार 639, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 241 लाभार्थियों ने पंजीकरण करवाया है।

भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

निवाई/लोकमत। भारतीय जनता पार्टी द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ बिजली की दरे बढाने, पानी की समस्या, अपराधिक मामलो मे वृद्धि, लचर कानून व्यवस्था, परीक्षाओ मे हो रही धांधली व भ्रष्टाचार को लेकर शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी विधानसभा क्षेत्र निवाई पीपलू के कार्यकर्ताओं द्वारा राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी रविकांत सिंह को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया कि प्रदेश में बिजली की दरे बढ़ रही है, पानी की समस्या, अपराधिक मामलो मे वृद्धि, लचर कानून व्यवस्था, परीक्षाओ मे हो रही धांधली व भ्रष्टाचार असीमित रूप से वृद्धि कर रहा है। निवाई विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न ग्राम में सड़कों का निर्माण अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है ग्रामीण जनता त्रस्त है। आपराधिक मामलों में निरंतर वृद्धि हो रही है। गोकशी व गौ तस्करी जैसे मामले बढ़ते जा रहे हैं प्रशासन गुनहगारों की जगह निर्दोषों को प्रताड़ित कर रहा है। प्रदेश में जब से कांग्रेस सरकार बनी है तब से दलितों पर अत्याचार निरंतर वृद्धि दिखाई दी है।

आरटीडीसी की टीम पहुंची अजमेर : माइस सेंटर एवं इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स के लिए जमीन चयनित करने हेतु किया दौरा

अजमेर/लोकमत। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार के बजट 2022-23 की घोषणा की क्रियान्विती हेतु आज राजस्थान पर्यटन विकास निगम की टीम ने होकरा में माइस सेंटर एवं बूढ़ा पुष्कर क्षेत्र में इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स के लिए स्थान का चयन के लिए जिला प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ दौरा कर एवं मौका मुआयना किया।

राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष एवं राज्य मंत्री धर्मेंद्र राठौड़ ने पत्रकारों को बताया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा के अनुसार 100 करोड़ की लागत से बनने वाले माइस सेंटर एवं बूढ़ा पुष्कर में 25 करोड़ की लागत से बनने वाले इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स के निर्माण के लिए राजस्थान पर्यटन विकास निगम को नोडल एजेंसी बनाया है! आज आरटीडीसी की टीम जिला प्रशासन के आला अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ होकरा एवं बूढ़ा पुष्कर क्षेत्र का दौरा कर स्थान चयन की प्रक्रिया शुरू की होकर में 30 बीघा माइस सेंटर के लिए एवं बूढ़ा पुष्कर में इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स के लिए जमीन का मौका मुआयना किया। निगम अध्यक्ष राठौड़ ने बताया कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम जैसलमेर में 2500 बीघा क्षेत्रफल में लगभग 15 सौ करोड़ रुपए की लागत से ढोला मारु टूरिस्ट कंपलेक्स का निर्माण करेगी जिसमें देसी एवं विदेशी पर्यटकों को अंतराष्ट्रीय मानकों की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने पुष्कर विकास प्राधिकरण के गठन की संरचना प्रारंभ कर दी है एवं राजस्थान सरकार ने आमेर विकास प्राधिकरण का प्रशासनिक कार्य कला एवं संस्कृति विभाग के अधीन दे रखा है इसी तर्ज पर पुष्कर विकास प्राधिकरण का प्रशासनिक कार्य राजस्थान पर्यटन विकास निगम को दिया है पुष्कर विकास प्राधिकरण के गठन से पुष्कर का समुचित विकास होगा! पुष्कर विकास प्राधिकरण के गठन के लिए मुख्य सचिव उषा शर्मा अतिरिक्त मुख्य वित्त सचिव अखिल अरोड़ा पर्यटन सचिव गायत्री राठौड़ राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष एवं राज्य मंत्री धर्मेंद्र राठौड एवं प्रबंध निदेशक वीपी सिंह आदि की समन्वय समिति बनाई है यह समिति समय-समय पर बैठक कर पुष्कर विकास प्राधिकरण की गठन करेगी। उन्होंने बताया कि बूढ़ा पुष्कर के पास नेडलिया में साढे 12 बीघा क्षेत्रफल में 100 बिस्तर का जिला स्तरीय चिकित्सालय का निर्माण का कार्य शीघ्र प्रारंभ कर दिया जाएगा।

राठौड़ ने बताया कि तीर्थ सरोवर पुष्कर में गंदे पानी की आवक को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर निर्माण कार्य जारी है एवं मानसून आने से पूर्व कार्य पूर्ण किया जाएगा।

इस अवसर पर राजस्थान पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक विजयपाल सिंह (ढूस), कार्यकारी निदेशक माधव शर्मा अभियंता शेर सिंह पर्यटन विभाग के उपनिदेशक अजय शर्मा प्रदुमन सिंह बलवीर सिंह चौहान अजमेर डेयरी के सदर रामचंद्र चौधरी पूर्व विधायक डॉ श्री गोपाल बाहेती डॉ राजकुमार जयपाल एसडीएम पुष्कर निखिल कुमार तहसीलदार संदीप चौधरी अजमेर विकास प्राधिकरण के सचिव अमानुल्लाह खान तहसीलदार आबिद अली खान भु निरीक्षक सुरेश बाला मनोज सेठी लक्ष्मीनारायण मनीष कुमार मिर्धा शिव कुमार बंसल नोरत गुर्जर हेमंत जोधा अरुण पाराशर धीरज जादम ओमप्रकाश डोल्या बैजनाथ पाराशर नरेश सत्यावना हमीद चीता चंद्रशेखर बालोटिया नकुल खण्डेलवाल विश्राम चौधरी एडवोकेट सम्राट सहित जिला प्रशासन के आला अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

भाजपा कार्यकर्ताओं ने उपखंड कार्यालय पर राज्य सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन

राज्यपाल के नाम दिया ज्ञापन

खेतड़ी/लोकमत। राज्य सरकार द्वारा बिजली दरों में बढ़ोतरी करने पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उपखंड कार्यालय में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए नायब तहसीलदार रमेश शर्मा को राज्यपाल के नाम इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर के नेतृत्व में ज्ञापन दिया । ज्ञापन में बताया कि कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणापत्र में बिजली की दरों में किसी भी प्रकार की बढोतरी नहीं करने का वादा किया था लेकिन सरकार में आने के बाद बिजली की दरों में बढोतरी कर राज्य की जनता को लूटने का काम किया है तथा 2018 में भाजपा की पूर्ववर्ती सरकार के फ्यूल सरचार्ज 18 पैसे प्रति यूनिट था उसे बढ़ाकर 60 पैसे प्रति यूनिट कर दिया गया और 2018 में बिजली की दरें 5.55 पैसे प्रति यूनिट हुआ करती थी उसे बढ़ाकर 11.90 पैसे प्रति यूनिट कर दी गई। है। इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर ने कहा कि जब से राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी तभी से बिजली और पेयजल की समस्या ने भयावह रूप ले लिया है राज्य की जनता पीने की पानी की बूंद- बूंद के लिए तरस रही है और राज्य सरकार के नुमाइंदे केवल झूठी वाहवाही लूटने में लगे हुए है । ज्ञापन के दौरान पूर्व नगरपालिका चेयरमैन विजेश शाह, सत्यनारायण भार्गव,गजेंद्र पारीक,कैलाश स्वामी,डॉक्टर सोमदत्त भगत, पार्षद नगेंद्र सोडा,विद्याधर सैनी, शेरसिंह निर्वाण,गजानंद कुमावत, नंदकिशोर चौकड़ीवाला, रोहिताश्व मणकस, एडवोकेट अजीत तंवर, एडवोकेट विश्वनाथ अग्रवाल, एडवोकेट महेंद्र छाबड़ी, निखिल शर्मा, नरेंद्र शर्मा, राम सिंह आदि कार्यकर्ता मौजूद थे।

राजस्व टीम ने हटवाए अतिक्रमण

निवाई/लोकमत। गांव पहाड़ी में प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान आम रास्तों की शिकायत पर उपखंड अधिकारी रविकांत के नेतृत्व में रास्तों से प्रभावशाली व्यक्तियों के अतिक्रमण को हटवाए। एसडीएम रविकांत सिंह ने बताया कि प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत गांव पहाडी में ग्राम वासियों द्वारा आम रास्तों में से अतिक्रमण हटाने की लिखित शिकायत की। ग्रामीणों ने रास्ते खुलवाकर आमजन की सुनवाई की अपील की। ग्रामीणों की शिकायत पर अतिक्रमण हटाने के लिए तहसीलदार अजीत कुमार बुंदेला एवं नायब तहसीलदार कुलदीप सिंह के नेतृत्व में राजस्व टीम गठित कर दी गई। टीम ने ग्रामीणों के समक्ष आम रास्तों का सीमाज्ञान कर तत्काल मौके से अतिक्रमण हटवाए गए। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत गांव पहाडी से नाहरवाड़ी जाने वाले रास्ते से करीब दो किलोमीटर अतिक्रमण राजस्व टीम द्वारा हटाया गया। उक्त रास्ते में रास्ते में करीब 30 साल पुराना अतिक्रमण था। इसी प्रकार राजस्व टीम ने गांव पहाडी से अभयपुरा जाने वाले रास्ते, गांव पहाडी से बीडा की तरफ जाने वाले मार्ग, गांव पहाडी से बैरवा ढाणी की ओर जाने वाले रास्ते तथा बालाजी मंदिर से खंडवा जाने वाले आम रास्ते से अतिक्रमण हटवा दिए।

पीटीईटी परीक्षा 21 मई को, परीक्षार्थियों को दो घंटे पहले पहुंचना होगा परीक्षा केन्द्र, सुबह 10 बजे बाद नहीं मिलेगा प्रवेश

प्रदेशभर के 1494 केन्द्रों पर 5 लाख 21 हजार से ज्यादा अभ्यर्थी देंगे

पहली बार पीटीईटी अभ्यर्थी परीक्षा के बाद अपने ले जा सकेंगे प्रश्न-पत्र एवं ओएमआर की कार्बन कॉपी

जयपुर/लोकमत।

बांसवाड़ा स्थित गोविंद गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय द्वारा 21 मई, 2023 (रविवार) को प्रदेशभर में आयोजित होने वाली पीटीईटी परीक्षा-2023 में 5 लाख 21 हजार 576 अभ्यर्थी भाग्य आजमाएंगे। 1494 केन्द्रों पर दो वर्षीय बीएड हेतु 3 लाख 42 हजार 873 एवं चार वर्षीय बीएड हेतु 1 लाख 78 हजार 703 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे।

परीक्षा से एक घंटे पूर्व बंद हो जाएंगे परीक्षा केन्द्र के गेट : पीटीईटी जयपुर जिला संयोजक एवं प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय जयपुर श्रीमती डॉ. अल्पना व्यास ने बताया कि परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र पर प्रातः 9 बजे पहुंचना होगा। सुबह 10 बजे परीक्षा केन्द्रों के गेट बंद हो जाएंगे जिसके बाद किसी भी परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

परीक्षार्थियों को केन्द्र में इन निर्देशों का रखना होगा ध्यान : परीक्षा के राज्य समन्वयक श्री मनोज पण्डया ने बताया कि अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र के अंदर केवल प्रवेश पत्र, फोटोयुक्त पहचान पत्र, नीले या काले रंग का बॉलपेन, पानी की पारदर्शी बोतल ही ले जा सकेंगे। पुरुष अभ्यर्थी आधी बांह की की शर्ट/कुरता, पेंट एवं स्लीपर तो वहीं महिला अभ्यर्थी आधी बांह का कुरता/टीशर्ट/ब्लाउज, पेंट, सलवार सूट, साड़ी, स्लीपर एवं बालों में साधारण रबर बैंड लगाकर केन्द्र में आ सकेंगे। परीक्षा से जुड़ी जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9414271588 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

जयपुर में 146 केन्द्रों पर होगा परीक्षा का आयोजन : जयपुर जिले में 21 मई को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक 146 केन्द्रों पर कुल 67 हजार से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा सम्मिलित होंगे। दो वर्षीय बीएड हेतु 51 हजार 986 एवं चार वर्षीय बीएड हेतु 15 हजार 945 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है।